चर्चा की | कर्मचारियों की समस्याओं पर हुआ गंभीर मंथन

दपूमरेमसं के प्रतिनिधि मंडल ने डीआरएम के समक्ष रखी समस्याएं

शहडोल, नवभारत । दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को मंडल सचिव प्रोम्पी सिंह के नेतृत्व में मंडल रेल प्रबंधक बिलासपुर से उनके शहडोल आगमन के दौरान मिला। प्रतिनिधिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न ज्वलंत समस्याओं से डीआरएम को अवगत कराया। मंडल रेल प्रबंधक ने सभी समस्याओं को अत्यंत गंभीरता से सुना, प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से चर्चा की तथा संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। इस अवसर पर मंडल सचिव श्री प्रोम्पी सिंह द्वारा डीआरएम का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया।

बैठक में प्रमुख रूप से रनिंग कर्मचारियों को थर्ड लाइन का लाभ नहीं मिलने, इससे उत्पन्न समस्याओं तथा उनके शीघ्र समाधान पर चर्चा हुई। डीआरएम ने इसे महत्वपूर्ण विषय मानते हुए स्पर्श के माध्यम से त्वरित समाधान का आश्वासन दिया।इसके अतिरिक्त विभिन्न खंडों में नामित कर न्यूनतम 120 किलोमीटर माइलेज सुनिश्चित करने, शहडोल के कर्मचारियों को ट्राइबल अलाउंस दिलाने, तथा अवकाश के बाद जारी की गई पनिशमेंट के मामलों में वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता से चर्चा कर कंसीडर करने का भरोसा दिलाया गया। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि हर माह डीपी बैच भेजे जाएंगे और आगामी छह महीनों में पैनल में शेष सभी कर्मचारियों की डीपी कर प्रमोशन प्रक्रिया तेज की जाएगी। विशेष रूप से शहडोल के कर्मचारियों को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया गया।

बैठक में मंडल के कोचिंग कैडर के रिव्यू की मांग भी रखी गई। साथ ही शहडोल के चिकित्सक द्वारा फिट व सिक सर्टिफिकेट जारी करने के विषय में डीआरएम ने स्पष्ट किया कि जेनुइन मामलों में बीमार रनिंग स्टाफ को जबरन ड्यूटी पर नहीं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि यह रेलवे संरक्षा के साथ खिलवाड़ है। इस संबंध में चिकित्सक से बात करने का भी आश्वासन दिया गया।इसके अलावा लॉन्ग हॉल का फॉर्मेशन पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था एवं सुरक्षित चेकिंग पथ वाले स्थान पर करने की मांग भी रखी गई।

बैठक के अंत में मंडल रेल प्रबंधक ने सभी विषयों पर सकारात्मक चर्चा कर समाधान का भरोसा दिलाया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर संघ ने कर्मचारी समस्याओं को गंभीरता से सुनने और समाधान हेतु रुचि दिखाने के लिए डीआरएम का आभार व्यक्त किया तथा आशा जताई कि उनके नेतृत्व में कर्मचारी संरक्षा एवं सुरक्षा के साथ निर्भय होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे। प्रतिनिधिमंडल में एन.के. चौबे, सतीश शर्मा, अमित शर्मा, अवधेश सिंह, तरुण साहू, सियाराम शाह, लोकपाल लोधी, अंकित शर्मा, आशीष कुमार रॉय, सुनील साहू, शुभम बर्मन सहित अनेक कर्मचारी शामिल रहे।

ग्रामीण अंचलों में शुरू हुई 'स्वच्छता साथी, वॉश ऑन व्हील' सेवा

स्वच्छता से रोजगार की नई पहल

शहडोल, नवभारत । ग्रामीण स्वच्छता को सुदृढ़ करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में शहडोल जिले में एक अभिनव पहल की गई है। 'स्वच्छता साथी वॉश ऑन व्हील' नामक यह सेवा मांग एवं पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित एक ऑनलाइन और मोबाइल एप आधारित व्यवस्था है, जिसके माध्यम से अब ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों की नियमित एवं पेशेवर साफ-सफाई संभव हो सकेगी। इस सेवा के तहत आम नागरिक, घर के मुखिया अथवा किसी संस्था के प्रमुख मोबाइल एप के माध्यम से शौचालय की साफ-सफाई हेतु स्वच्छता साथी को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। रिक्वेस्ट प्राप्त होते ही निर्धारित तिथि व समय पर स्वच्छता सेवा उपलब्ध कराई जाती है।वॉश ऑन व्हील सेवा की मांग एवं पूर्ति की दैनिक रिपोर्टिंग जिला समन्वयक द्वारा की जा रही है, जिसकी जनपदवार समीक्षा सीईओ जिला पंचायत द्वारा की जाती है। वहीं ब्लॉक समन्वयकों द्वारा स्वच्छता साथियों को तकनीकी सहयोग प्रदान करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संस्थानों, वाहन शोरूम, वर्कशॉप, पेट्रोल पंप, ढाबा, रिसॉर्ट, मैरिज गार्डन आदि स्थानों पर जाकर सेवा का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

759 गांव जुड़े, 21 सेक्टरों में सेवा प्रारंभ

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित सफाई कर्मियों की कमी को देखते हुए यह पहल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल श्री शिवम प्रजापति के निर्देशानुसार प्रारंभ की गई। जिले के 05 ब्लॉकों से संबद्ध 30 क्लस्टर का निर्माण कर अब तक 759 ग्रामों को इस सेवा से जोड़ा जा चुका है।ऑनबोर्ड किए गए 36 स्वच्छता साथियों में से 21 स्वच्छता साथियों को प्रशिक्षित कर 21 सेक्टरों में कार्य आवंटित कर सेवा प्रारंभ कर दी गई है। शेष 09 सेक्टरों में 15 जनवरी तक कार्य प्रारंभ कर जिले के शत-प्रतिशत गांवों में यह सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक जिले में 510 ऑनलाइन मांगें प्राप्त हो चुकी हैं, जिनका निराकरण स्वच्छता साथियों द्वारा निर्धारित स्लॉट के अनुसार किया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से शहडोल जिले के स्वच्छता साथी अब तक 45,000 रुपये की आय अर्जित कर चुके हैं, जिससे यह योजना स्वच्छता के साथ-साथ रोजगार का सशक्त माध्यम बनकर उभरी है।

मोबाइल एप से आसान बुकिंग

जिला समन्वयक दिनेश मिश्रा ने बताया कि वॉश ऑन व्हील सेवा के लिए मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए क्यूआर कोड के माध्यम से प्ले स्टोर से एप डाउनलोड कर सरल प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। एप में गांव चयन, शौचालय के प्रकार (घरेलू, संस्थागत, सामुदायिक), संख्या, दिनांक व समय दर्ज कर अनुरोध भेजा जा सकता है, जो सीधे संबंधित स्वच्छता साथी तक पहुंचता है। 'स्वच्छता साथी वॉश ऑन व्हील' सेवा ग्रामीण अंचलों में घरेलू, संस्थागत एवं सामुदायिक शौचालयों की साफ-सफाई के लिए एक स्मार्ट, आधुनिक और मांग आधारित समाधान प्रदान करेगी। यह पहल न केवल स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाएगी, बल्कि ग्रामीण युवाओं के लिए स्थायी आजीविका का साधन भी सिद्ध हो रही है।

युवा मतदाता सूची में कराए नाम दर्ज, निभाएं लोकतांत्रिक जिम्मेदारी

कन्या महाविद्यालय शहडोल में लगाया गया विशेष मतदाता पंजीकरण शिविर

शहडोल, नवभारत । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवा मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने हेतु शैक्षणिक संस्थानों में विशेष मतदाता पंजीकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी अनुक्रम में शासकीय इंदिरा गांधी कन्या महाविद्यालय शहडोल में लगाए गए विशेष मतदाता पंजीकरण शिविर का उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमृता गर्ग ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित छात्राओं को अवगत कराया कि 1 जनवरी 2026 तक की अर्हता पर 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवा अपना नाम मतदाता सूची में फॉर्म 6 भरकर जुड़वाए और अपनी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी निभाएँ। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए सम्बंधित वेबसाइट या अपने नजदीकी बूथ लेवल ऑफिसर से भी संपर्क कर सकते है। जिले भर की शैक्षणिक संस्थानों में मतदाता पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया।

उप मुख्यमंत्री ने सोनोग्राफी मशीन का फीता काटकर किया शुभारंभ

बुढार क्षेत्र के जरूरतमंद मरीजों को अब सुलभ होगी सोनोग्राफी की सुविधा

शहडोल, नवभारत । मध्यप्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री तथा शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने जिले के प्रवास के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढ़ार में नवीन सोनोग्राफी मशीन का फीता काटकर शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि बुढार क्षेत्र के जरूरतमंद मरीजों को स्थानीय स्तर पर अब सोनोग्राफी की सुविधा सुलभ हो सकेंगी। इससे मरीजों को जिला मुख्यालय अथवा अन्य शहरों की ओर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और समय व धन दोनों की बचत होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन को बेहतर एवं सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उप मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बुढार के विभिन्न वार्डों का भी निरीक्षण कर उपलब्ध संसाधनों की जानकारी प्राप्त की। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों और परिजनों से चर्चा कर स्वास्थ्य केंद्र में दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान विधायक जयसिंह मरावी, सदस्य जिला योजना समिति अमिता चपरा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश मिश्रा सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

विश्व हिंदी दिवस दिवस पर काव्य गोष्ठी का आयोजन

हिन्दी भाषा की बुनावट में भारतीय संस्कृति के महीन धागे बुने हैं- विभागाध्यक्ष हिन्दी

शहडोल, नवभारत । पंडित शंभूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय, शहडोल के हिन्दी विभाग में विश्व हिन्दी दिवस के अवसर पर एक सारगर्भित काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य हिन्दी भाषा की सांस्कृतिक चेतना, मानवीय मूल्यों और साहित्यिक परंपरा को रेखांकित करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विभागाध्यक्ष डॉ. गंगाधर ढोके ने मानवीय संबंधों पर आधारित अपनी ग़ज़ल प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की भाषा की बुनावट में वहाँ की संस्कृति के महीन धागे बुने होते हैं, और हिन्दी इस दृष्टि से अत्यंत समृद्ध भाषा है। डॉ. संगीता धुर्वे, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) ने अपने विचारों में हिन्दी को जन-जन की संवेदना की भाषा बताया। उनकी काव्य पंक्तियों में लोकजीवन और स्त्री अनुभूतियों की सशक्त अभिव्यक्ति देखने को मिली।डॉ. दिलीप कुमार तिवारी ने हिन्दी साहित्य की दार्शनिक और सांस्कृतिक परंपरा पर प्रकाश डाला। उनकी प्रस्तुति में भाषा और जीवन के गहरे संबंधों की मार्मिक झलक दिखाई दी।

डॉ. लोकेश साहू ने हिन्दी की समकालीन भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हिन्दी आज भी समाज को जोड़ने वाली सबसे प्रभावी भाषा है। वीरेन्द्र कुर्मी ने अपनी काव्य पंक्तियों में सामाजिक यथार्थ और मानवीय सरोकारों को स्वर दिया। उनकी प्रस्तुति श्रोताओं के लिए विचारोत्तेजक रही।आयुष द्विवेदी ने युवा चेतना और हिन्दी के भविष्य पर केंद्रित विचार रखे। उनकी कविता में आशा, संघर्ष और नवचेतना का स्वर स्पष्ट था।मंजुला तिवारी ने साहित्य को संस्कार निर्माण का माध्यम बताया। उनकी रचना में भाषा की कोमलता और भावों की गहराई झलकती रही।कार्यक्रम में हिन्दी विभाग के विद्यार्थियों अंकिता रस्तोगी, दिशा गौतम, सुप्रिया तिवारी, कल्याणी तिवारी, प्रिया गुप्ता, सुहानी सोनी, शाहीन अंसारी, चंद्रकली, रिंकी बैगा, सोनाक्षी गौतम, ओमप्रकाश मेहरा, हेमलता धुर्वे, संयोजना सिंह एवं शिल्पी घसिया ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से हिन्दी के प्रति अपने भाव और विचार व्यक्त किए, जिन्हें उपस्थितजनों ने सराहा।कार्यक्रम का सफल संचालन मधु गोले (एम.ए. हिन्दी) ने किया, जबकि अंत में प्रिया सिंह (बी.ए. हिन्दी) ने सभी अतिथियों, प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

राष्ट्रीय शालेय क्रिकेट प्रतियोगिता हेतु वाषु गुप्ता का चयन

शहडोल नवभारत। राजस्थान के सीकर में 19 जनवरी से 24 जनवरी तक आयोजित होने वाली 69 वीं राष्ट्रीय शालेय क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए टाइम्स पब्लिक स्कूल शहडोल में अध्ययनरत वाषु गुप्ता का चयन किया गया। चयन होने पर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण शहडोल संभाग शहडोल उमेश कुमार धुर्वे, जिला शिक्षा अधिकारी शहडोल फूल सिंह मारपाची, सहायक संचालक आर के मंगलानी, सहायक संचालक खेल रईस अहमद ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। सहायक संचालक रईस अहमद ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मध्य प्रदेश टीम का प्री नेशनल कोचिंग कैंप 12 से 16 जनवरी 2026 तक जिला शिक्षा अधिकारी जिला छतरपुर द्वारा किया जाएगा।

कोषालय अधिकारी की हठधर्मिता से अब तक भुगतान शेष

सेवानिवृत्त प्राचार्य के स्वत्वों के भुगतान में लगा रहे अड़ंगा

गोहपारू, नवभारत । शासकीय माडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय असवारी गोहपारू से 31जुलाई2025 को सेवानिवृत्त 102प्राचार्य शैल कुमार तिवारी के अर्जित अवकाश के नगदीकरण का भुगतान 3-4बार देयक प्रस्तुत किए जाने के वावजूद अभी तक नहीं किया गया जबकि 5माह बीत चुके हैं निश्चित ही कोषालय अधिकारी की मंशानुरूप मांग की पूर्ति नहीं हो पा रही जिससे भुगतान विलंबित किया जा रहा है जबकि कोषालय अधिकारी को मालूम है कि प्राचार्य को एक वर्ष में एक माह अर्जित अवकाश की पात्रता है क्योंकि यह पद विश्रामावकाश कर्मचारी की श्रेणी में नही आता फिर भी भुगतान करने में अड़ंगा पर अड़ंगा मात्र 1870850/रुपये मोटी रकम से कुछ पाने की मंशा परिलक्षित हो रही है जबकि इसी प्रकार के देयक बिना किसी अड़ंगा के इन्हीं साहब के द्वारा भुगतान किया जा चुका है ।

कोषालय अधिकारी डी पी मिश्रा को यह भलीभांति मालूम है कि उक्त रकम की मासिक ब्याज 9000रुपये होती है इस प्रकार लगभग 36000नुकसान किया जा चुका है और अभी नुकसान की मंशा केवल कुछ पाने की प्रत्याशा से किया जा रहा है, जिससे व्यथित हो कर सेवानिवृत्त प्राचार्य द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर 2025को कलेक्टर शहडोल एवं 06 जनवरी 2026को संभागायुक्त शहडोल के समक्ष जनसुनवाई में भुगतान हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है । प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसो सिएशन संभाग शहडोल के महासचिव ने कहा है कि यदि इस पर भी भुगतान नहीं किया गया तो निश्चित ही एसोसिएशन को कोषालय अधिकारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ सकता है।

सरकार की तरफ से जांच दस्तावेजों के साथ हाईकोर्ट में पेश की गयी स्टेटस रिपोर्ट

मऊगंज हिंसा मामले में सीबीआई की जांच आवश्यक नहीं

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने मऊगंज में आदिवासियों परिवारों के साथ हुई हिंसा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष जांच संबंधित दस्तावेज के साथ स्टेटस रिपोर्ट पेश की गयी। सरकार की तरफ से बताया गया कि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है।

युगलपीठ ने सरकार की तरफ से पेश किये गये जवाब

पर याचिकाकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गयी है। रीवा हनुमना निवासी पूर्व विधायक सुखेन्द्र सिंह बन्ना की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि मऊगंज के ग्राम गडरा में आदिवासी परिवारों की भूमि खाली कराने को लेकर भू-माफियाओं ने मारपीट की थी। पूरे मामले के हिंसक रूप लेने के दौरान जमकर उपद्रव मचा था।

जिसमें ड्यूटी पर तैनात एक एएसआई की भी मौत हो गई थी। इसके बाद माफियाओं ने कई आदिवासी लोगों की हत्या कर दी, इतना ही नहीं एक ही परिवार के तीन लोग फांसी के फंदे पर लटके हुए भी पाये गये थे। आवेदक की ओर से कहा गया कि उक्त हिंसा में करीब आधा दर्जन लोगों की मौत हुई थी, वहीं करीब डेढ से दो सौ आदिवासी परिवार अपना घर बार छोडक़र गायब हो गये है, जिनका अब तक कुछ पता नहीं चला है। उक्त मामले की संबंधित अधिकारियों से लेकर उच्चाधिकारियों को शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिस पर सीबीआई जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट की शरण ली गई है। मामले में गृह विभाग के प्रमुख सचिव, डीजीपी रीवा, आईजी रीवा, कलेक्टर व एसपी मऊगंज, केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव व सीबीआई को पक्षकार बनाया गया है। युगलपीठ ने सुनवाई पश्चात सरकार को स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये थे। सरकार की तरफ से दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट पेश करते हुए बताया गया कि याचिका में लगाये गये आरोप निराधार है। सीबीआई पर पहले ही अतिरिक्त वर्क लोड है। ऐसी स्थिति में सीबीआई की जांच आवश्यक नहीं है।